

भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में महिला उद्यमियों की भूमिका

स्वप्निल चौहान*

* शोधार्थी, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना - लगभग सभी देशों की अर्थव्यवस्थाओं में महिलाओं के स्वामित्व वाले व्यवसाय अत्यधिक बढ़ रहे हैं। समाज में भूमिका और आर्थिक स्थिति के प्रति बढ़ती संवेदनशीलता के साथ महिलाओं की छिपी उद्यमशीलता क्षमताएं धीरे-धीरे बदल रही हैं। व्यवसाय में कौशल, ज्ञान और अनुकूलनशीलता महिलाओं के व्यवसाय-उद्यमों में उभरने के मुख्य कारण हैं। मीडिया के आगमन के साथ, महिलाएं अपने गुणों, अधिकारों और कार्य स्थितियों के बारे में भी जागरूक हैं। वे डिजाइनर, इंटीरियर डेकोरेटर, निर्यातक, प्रकाशक, परिधान निर्माता के रूप में फल-फूल रहे हैं और अभी भी आर्थिक भागीदारी के नए रास्ते तलाश रहे हैं। तदनुसार, पिछले दो दशकों के दौरान, बढ़ती संख्या में भारतीय महिलाओं ने उद्यमिता के क्षेत्र में प्रवेश किया है और वे धीरे-धीरे आज के व्यवसाय का चेहरा शाब्दिक और आलंकारिक रूप से बदल रही हैं। आधुनिक प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग, निवेश में वृद्धि, निर्यात बाजार में जगह तलाशने, दूसरों के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करने और संगठित क्षेत्र में अन्य महिला उद्यमियों के लिए रुझान स्थापित करने के लिए महिला उद्यमियों की सराहना की जानी चाहिए। हालांकि महिला उद्यमियों ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है, लेकिन तथ्य यह है कि वे पहले से कहीं अधिक योगदान देने में सक्षम हैं। पिछले दशक के दौरान महिला उद्यमिता को आर्थिक विकास के एक महत्वपूर्ण अप्रयुक्त स्रोत के रूप में मान्यता दी गई है। महिला उद्यमी अपने और दूसरों के लिए नई नौकरियाँ पैदा करती हैं। वे समाज को प्रबंधन, संगठन और व्यावसायिक समस्याओं के साथ-साथ उद्यमशीलता के अवसरों के दोहन के लिए विभिन्न समाधान भी प्रदान करते हैं।

महिला उद्यमी की परिभाषा - 'महिला उद्यमी' वह व्यक्ति है जो अपनी व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के लिए चुनौतीपूर्ण भूमिका स्वीकार करती है। कुछ सकारात्मक करने की तीव्र इच्छा उद्यमशील महिलाओं का अंतर्निहित गुण है, जो परिवार और सामाजिक जीवन दोनों में मूल्यों का योगदान देने में सक्षम है।

उद्देश्य :

1. महिला उद्यमियों को उनके व्यवसाय में प्रेरित करने वाले कारकों का आकलन करना।
2. भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में उनकी भूमिका का विश्लेषण करना।
3. महिला उद्यमियों के विकास के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को सामने लाना।

महिला उद्यमियों को प्रेरित करने वाले कारक - व्यवसाय की शुरुआत और सफलता में प्रेरणा एक महत्वपूर्ण कारक है। मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि व्यक्तिगत कार्य प्रदर्शन क्षमता का एक कार्य है और प्रेरणा आंतरिक और बाहरी दोनों उत्तोजनाओं से उत्पन्न होती है। दबाव और खिंचाव कारकों के कारण उत्पन्न प्रेरणाएं संभावित उद्यमी की अपेक्षाओं को उत्तोजित करती हैं। यह वह प्रेरणा है जो सीधे तौर पर उद्यमशीलता संबंधी निर्णयों को जन्म देती है। 'Push Factor' और 'Pull Factor' व्यक्तिगत उद्यमशीलता व्यवहार को निर्धारित करते हैं, किसी व्यक्ति की अपेक्षाओं को उत्तेजित करते हैं और उसका निर्माण करते हैं।

इस प्रकार महिला उद्यमियों के प्रेरक कारकों की पहचान करने की आवश्यकता प्रतीत होती है जो व्यवसाय शुरू करने के उनके निर्णय को जन्म देते हैं।

पुश कारक: पुश कारक वे कारक हैं जो आवश्यकताओं से संबंधित हैं जैसे (1) बेरोजगारी, (2) अतिरेक, (3) मंदी, (4) पर्याप्त पारिवारिक आय नहीं, (5) वर्तमान नौकरी से असंतोष, और (6) काम और घरेलू भूमिकाओं को समायोजित करने की आवश्यकता।

पुल कारक: उद्यमशील अवसर पैदा करने वाली एक संपन्न अर्थव्यवस्था से प्रेरित स्व-रोजगार बनने का निर्णय ऐसे कारकों से संबंधित है जैसे (1) स्वतंत्रता की आवश्यकता, (2) चुनौती की आवश्यकता, (3)) बेहतर वित्तीय अवसर, (4) आत्म-संतुष्टि, (5) खुद का मालिक बनने की इच्छा, (6) परिवार और काम में संतुलन बनाने का लचीलापन, (7) शौक विकसित करने की क्षमता, (8) व्यक्तिगत उपलब्धि और (9) रोल मॉडल और अन्य लोगों का प्रभाव (दोस्त और परिवार)।

भारत में महिला उद्यमियों की भूमिका और योगदान - भारत में, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यम क्षेत्र में महिलाओं का वर्चस्व है। सूक्ष्म उद्यम क्षेत्र में कार्यरत लोगों में 74 प्रतिशत महिलाएं शामिल हैं। कुटीर/हस्तशिल्प उद्योगों (सूक्ष्म उद्यम) में 65 प्रतिशत से अधिक महिलाएं खाद्य उत्पादों और पेय पदार्थों के प्रसंस्करण में लगी हुई थीं।

आर्थिक योगदान- महिलाओं की आर्थिक गतिविधियाँ अनौपचारिक व्यावसायिक समस्याओं से निपटने में विकास और दक्षता में सीधे योगदान देती हैं और गरीबी में कमी नीति निर्माताओं के लिए मुख्य मुद्दों में से एक है।

पूंजी निर्माण - उद्यमी औद्योगिक प्रतिभूतियों को जारी करके जनता की निष्क्रिय बचत जुटाते हैं। उद्योग में सार्वजनिक बचत के निवेश से राष्ट्रीय संसाधनों का उत्पादक उपयोग होता है। पूंजी निर्माण की दर बढ़ती है, जो

तीव्र आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है।

प्रति व्यक्ति आय में सुधार – भारत में महिला उद्यमी भी अवसरों का दोहन कर रही हैं। वे भूमि, श्रम और पूंजी जैसे अव्यक्त और निष्क्रिय संसाधनों को वस्तुओं और सेवाओं के रूप में राष्ट्रीय आय और धन में परिवर्तित करती हैं। वे देश के शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद और प्रति व्यक्ति को बढ़ाने में मदद करती हैं जो आर्थिक विकास को मापने के लिए महत्वपूर्ण मानदंड हैं।

रोजगार सृजन – भारत में महिला उद्यमी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। लघु उद्योग स्थापित करके वे लोगों को रोजगार देते हैं।

सामाजिक योगदान – महिला उद्यमी देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास और जीवन स्तर में सुधार की दिशा में भी योगदान दे रही हैं।

1. **संतुलित क्षेत्रीय विकास** – भारत में महिला उद्यमी आर्थिक विकास में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करती हैं। वे सरकार द्वारा दिए जाने वाले संसाधनों, रियायतों और सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करते हैं।

2. **जीवन स्तर में सुधार** – लघु उद्योगों की स्थापना से आवश्यक वस्तुओं की कमी को कम किया जा सकता है तथा नये उत्पाद लाये जा सकते हैं। इस देश में महिला उद्यमी बड़े पैमाने पर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन कर रही हैं और उन्हें कम दरों पर पेश कर रही हैं, जिसके परिणामस्वरूप जीवन स्तर में सुधार हो रहा है।

अन्य योगदान – महिला उद्यमी समाज की संस्कृति को बदलने में मुख्य भूमिका निभाती हैं। हमारे देश में महिलाएं घर से बाहर निकलकर स्वतंत्रता आदि की भावना विकसित करती हैं। इस प्रकार हमारे देश में महिला उद्यमी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण संरक्षण, बैकवर्ड और फॉरवर्ड एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं और ज़िंदगी में बदलाव के रूप में कार्य कर रही हैं, इस प्रकार देश की आर्थिक वृद्धि में योगदान दे रही हैं।

महिला उद्यमियों को विकसित करने के लिए भारत सरकार की पहल – आजादी के बाद से ही महिलाओं का विकास सरकार का नीतिगत उद्देश्य रहा है। सरकारी और गैर सरकारी निकायों ने स्व-रोजगार और औद्योगिक उद्यमों के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक योगदान पर अधिक ध्यान दिया है।

1. प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-56) में महिलाओं के लिए कई कल्याणकारी उपायों की परिकल्पना की गई। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना, महिला मंडलों का संगठन और सामुदायिक विकास कार्यक्रम इस दिशा में कुछ कदम थे।
2. दूसरी पंचवर्षीय योजना (1956-61) में, महिलाओं के सशक्तिकरण को गहन कृषि विकास कार्यक्रमों के समग्र दृष्टिकोण के साथ निकटता से जोड़ा गया था।
3. तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना (1961-66 और 1969-74) ने एक प्रमुख कल्याणकारी उपाय के रूप में महिला शिक्षा का समर्थन किया।
4. पाँचवीं पंचवर्षीय योजना (1974-79) में उन महिलाओं के प्रशिक्षण पर जोर दिया गया, जिन्हें आय और सुरक्षा की आवश्यकता थी। यह योजना अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक और भारत में महिलाओं की स्थिति पर समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के साथ मेल खाती है। 1976 में, सामाजिक कल्याण मंत्रालय के तहत महिला कल्याण और विकास

ब्यूरो की स्थापना की गई थी।

5. छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) में कल्याण से विकास की ओर एक निश्चित बदलाव देखा गया। इसने महिलाओं की संसाधनों तक पहुंच की कमी को उनके विकास में बाधा डालने वाले एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में पहचाना।
6. सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) में लैंगिक समानता और सशक्तिकरण की आवश्यकता पर जोर दिया गया। पहली बार, आत्मविश्वास पैदा करने, अधिकारों के संबंध में जागरूकता पैदा करने और बेहतर रोजगार के लिए कौशल प्रशिक्षण जैसे गुणात्मक पहलुओं पर जोर दिया गया।
7. आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) ने पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से, विशेषकर बुनियादी स्तर पर, महिलाओं को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया।
8. नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) ने एक महत्वपूर्ण रणनीति अपनाई जिसके अंतर्गत महिला उद्यमियों के लिए अनेक योजनाएं बनाई गईं।
9. दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) का लक्ष्य नारी सशक्तिकरण था। जिसके अंतर्गत महिला सशक्तिकरण नीति (2001) क्रियान्वित की गई और महिलाओं की उत्तारजीविता, सुरक्षा और विकास सुनिश्चित किया गया।
10. ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) का उद्देश्य महिलाओं को राजनीतिक, शैक्षिक, आर्थिक, कानूनी रूप से सशक्त बनाना है।
11. बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-2017) सभी महिलाओं की गरिमा और समानता सुनिश्चित करने के लिए है, जिससे उन्हें अपनी आर्थिक वृद्धि के माध्यम से अपनी पसंद, संसाधनों, सामाजिक धारणाओं और दृष्टिकोणों पर नियंत्रण हासिल करने में सक्षम बनाया जा सके। सभी राष्ट्रीय नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों को जन्म देकर सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता।

वर्तमान में, भारत सरकार के पास विभिन्न विभागों और मंत्रालयों द्वारा महिलाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित हैं।

1. एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआरडीपी),
2. खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी),
3. स्व-रोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण (ट्राइसेम),
4. प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई),
5. उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम (ईडीपी),
6. प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी)
7. महिला विकास निगम (डब्ल्यूडीसी),
8. ग्रामीण महिलाओं के गैर-कृषि उत्पादों का विपणन (महिमा),
9. गैर-कृषि विकास (ARWIND) योजनाओं में ग्रामीण महिलाओं को सहायता
10. व्यापार संबंधी उद्यमिता सहायता और विकास

निष्कर्ष – भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति स्पष्ट रूप से परिवर्तन की प्रक्रिया में है और भविष्य के सामाजिक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। यह शोध पत्र महिला उद्यमिता समाज में महिलाओं की स्थिति और उसी समाज में उद्यमिता की भूमिका दोनों के बारे में है। भारतीय महिलाएं देश की सामाजिक-आर्थिक प्रगति शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

महिलाओं को सशक्त बनाया जाना चाहिए ताकि वे भारत को गौरव की ओर ले जा सकें। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को अच्छे अवसरों तक पहुंच प्रदान की जानी चाहिए ताकि वे सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन ला सकें और देश के विकास में योगदान दे सकें।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. लखन लाल चौकचे (2021) - महिलाओं के अधिन विकास में जयाविना विकास कार्यक्रमों के ओगवान का अध्ययन करना (इंदौर संभाग के विशेष संदर्भ में)
2. सुजाता परी अहिरवाल, प्रो. जिनेन्द्र कुमार जैन (2014) - महिला उद्यमिता और सरकारी भूमिका: वर्तमान परिदृश्य भारत के संदर्भ में।

3. Ritwik Saraswat and Ramya lathabahvan - A Study on women Entrepreneurship in India
4. Vanita yadar and Jeemal unni - Women Entrepreneurship: research review and future Directions

Websites:-

1. www.inspirajournals.com
2. www.jetir.org
3. www.startupindia.gov.in
4. www.researchgate.net
5. www.econstor.ev
6. www.worldwidejournals.com
